

नागरिकता संशोधन कानून बहस को बढ़ावा

नागरिकता संशोधन कानून-सीएए पर अमित शाह के बयान ने बहस को बढ़ावा दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून-सीएए का क्रियान्वयन होगा। इसने जोरदार बहस व उत्तमानों को हवा दे दी है। दिसंबर, 2019 में लाए जाने के बाद से ही सीएए विवादों का विषय बन गया है। इसका उद्देश्य पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के उद्योगिता अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। उस समय सीएए के विरोध और अल्पसंख्यकों को छोड़ देशों की अधिकार प्रभावित होते थे। इस बारे फिर शाह द्वारा सीएए के क्रियान्वयन पर दिए बयान से संदेह और चर्चा को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय नागरिकता रिजिस्टर-एनआरसी से इसके जुड़ाव के कारण खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ संभावित भेदभाव व पृथक्करण के भय से राष्ट्रीयों विरोध हुआ था। इन प्रवर्षणों पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि सीएए का उद्देश्य विस्तृत समुदाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है और इसका उद्देश्य केवल पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित स्वर्ग प्रदान करना है। लेकिन इसके बावजूद कानून से जुड़ा विवाद बना रहा जिसके कारण क्रियान्वयन को अनिवार्यता काल तक ताल दिया गया। शयद उस समय सरकार ने इस ठंडे बर्से में डालाना ठीक समझा। इस बीच अन्य मुद्रे समाने आ गए और सीएए को लगभग भुला दिया गया। लेकिन अमित शाह के बयान से यह एक बारे फिर यह केंद्रीय स्थान पर आ गया है।

समर्थकों का तर्क है कि सीएए एक मानवीय विचार है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का समान कर रहे हैं लोगों को शरण देने का प्रत्यावर करता है। उनका कहना है कि यह भारत द्वारा उत्तीर्णित समुदायों को शरण देने तथा धार्मिक स्वतंत्रता सिद्धान्तों के पालन की परंपरा के अनुसार है। दूसरी ओर आलोचकों को भारत के 'पंथनिषेच' हाँचे पर कानून के संभावित प्रभाव के बारे में चिना है। उनका तर्क है कि चिनीय निकाल के अन्देखा कर सबके साथ समान व्यवहार के सिद्धान्त को अनदेखी करता है। आलोचकों को डर है कि इससे संविधान के पंथनिषेच स्मृताधारों को चुनौती देने का उदाहरण स्थापित हो सकता है। इसके साथ ही सीएए निकालों से एनआरसी से जुड़ा है और इस प्रक्रिया का उद्देश्य अवैध आप्रवासियों की पहचान कर उनके देश से बाहर निकालना है। यह तथ्य उत्तरवाहीय है कि अन्यतों में चुनौती दी गई ही और न्यायालयों ने उसे संविधान-सम्मत माना है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसका फिलहाल देश में एनआरसी लागू करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए सीएए को उसके साथ जोड़ करना अनुचित है। अमित शाह ने हालिया बयान विधानसभा चुनावों में मतदान के अन्तिम दिन पश्चिम बंगाल में दिया, इसलिए इस चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से देखना भी उत्तिन नहीं है। इस तथ्य से भी इनका नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में हिंदुओं व सिखों का सुनियोजित ढंग से सफाया या धर्मान्वयन कराया गया है जिससे उनकी संख्या बहाने लगभग नगण्य हो गई है। ऐसे में उत्तीर्णित हिंदुओं और सिखों को भारत में शरण देने का कानून भारत की परंपरा के अनुरूप है तथा यह किसी प्रकार देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है।

दिवेश सूर
(लेखक, कौशल विकास
क्षेत्र से सबद्ध हैं)

वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-पीएमकेवीवाई के अंतर्गत पिछले सात साल में 13.7 मिलियन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन इसमें से केवल 18 प्रतिशत या 2.4 मिलियन उम्मीदवारों ही रोजगार प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

समिति ने इस कम 'प्लेसमेंट द' पर चिनाप्रकट की है। समिति ने ऐसे के उपयोग में कमी, ढांचागत कमियों, ड्रापआउट, उद्योगों से संपर्क के अभाव तथा राज्य की एक समुचित संलग्नता के अभाव को महत्वपूर्ण सम्पर्कों माना है।

कार्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। वर्तमान समय में भारत के 530 मिलियन कार्यवाल के केवल 2.4 प्रतिशत हैं जिनकी संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर केवल 20 प्रतिशत है। इसकी अर्थ है कि बहुत संख्या के सर्वोच्च प्लेसमेंट दर 35.1 प्रतिशत है और इसके बाद 34.6 प्रतिशत के साथ युद्धचेरी दूसरे स्थान पर है। हरियाणा और पंजाब भी बहुत पीछे नहीं हैं। जिनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई के लिए विकास योजना-पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर केवल 20 प्रतिशत है। इसकी अर्थ है कि बहुत संख्या के सर्वोच्च प्लेसमेंट दर 35.1 प्रतिशत है और इसके बाद 34.6 प्रतिशत के साथ युद्धचेरी दूसरे स्थान पर है। हरियाणा और पंजाब भी बहुत पीछे नहीं हैं। जिनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर केवल 20 प्रतिशत है। इसकी अर्थ है कि बहुत संख्या के सर्वोच्च प्लेसमेंट दर 35.1 प्रतिशत है और इसके बाद 34.6 प्रतिशत के साथ युद्धचेरी दूसरे स्थान पर है। हरियाणा और पंजाब भी बहुत पीछे नहीं हैं। जिनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर केवल 20 प्रतिशत है। इसकी अर्थ है कि बहुत संख्या के सर्वोच्च प्लेसमेंट दर 35.1 प्रतिशत है और इसके बाद 34.6 प्रतिशत के साथ युद्धचेरी दूसरे स्थान पर है। हरियाणा और पंजाब भी बहुत पीछे नहीं हैं। जिनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी बीच संख्या 1.59 मिलियन है। लेकिन राज्य में उनकी प्लेसमेंट दर क्रमशः 31.7 व 29.6 प्रतिशत है।

पीएमकेवीवाई को स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यक

